

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

आपराधिक अपील संख्या (खंडपीठ) 385/2015

[विद्वान जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-V, गिरिडीह द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 375/2010 में पारित दोषसिद्धि के दिनांक 20.04.2015 के निर्णय एवं सजा के दिनांक 21.04.2015 के आदेश के विरुद्ध]

1. पप्पू रबीदास उर्फ एतवारी दास, पिता- पप्पू दास,
2. बंधनी देवी उर्फ बुधनी देवी, पति- पप्पू दास, दोनों लखारी, डाकघर-लखारी, थाना-गिरिडीह (एम), जिला-गिरिडीह के निवासी

अपीलकर्ता

बनाम

झारखंड राज्य

विरोधी पक्ष

माननीय न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद

माननीय न्यायमूर्ति नवनीत कुमार

अपीलकर्ता की ओर से : श्री एस.के. मूर्ति, अधिवक्ता

राज्य की ओर से : श्री विश्वनाथ रॉय, सहायक लोक अभियोजक

सी.ए.वी. 23/11/2023

19/12/2023 को

सुनाया गया

न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद के अनुसार:

1. तत्काल अपील, जो कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के तहत दायर की गई है, को 20.04.2015 की दोषसिद्धि के निर्णय और 21.04.2015 के सजा के आदेश के खिलाफ प्रस्तुत

किया गया है, जिसे सत्र न्यायालय के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-V, गिरिडीह द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 375/2010 में पारित किया गया है, जिसमें अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और उसे जीवन भर की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है तथा ₹5000/- का जुर्माना भी लगाया गया है और यदि जुर्माना अदा नहीं किया जाता है तो उसे दो साल की अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।

2. इस न्यायालय ने दोषसिद्धि और सजा के आदेश की वैधता और उचितता की जांच करने से पहले अभियोजन मामले की पृष्ठभूमि का उल्लेख करना उचित समझा, जैसा कि सूचना देने वाले की फर्दबयान में उल्लेखित है, जो निम्नलिखित है:

3. सूचना देने वाली रेनू देवी ने अधिकारी-इन-चार्ज, मफ्फसिल थाना, गिरिडीह को लिखित रिपोर्ट दी जिसमें उन्होंने कहा कि उनके पति गुलाब मंडल और एक पप्पू दास साझेदारी में ईंटों का व्यवसाय चला रहे थे जिसके लिए उनके पति और ससुर ने पप्पू दास को एक लाख रुपये (₹1,00,000/-) दिए थे और यह सहमति हुई थी कि वे ईंट भट्टा में पैसे का निवेश करेंगे और काम पप्पू दास करेगा। व्यवसाय चलाने के दौरान पप्पू दास पर ₹30,000/- बकाया हो गए और पैसे मांगने पर पप्पू दास उन्हें मारने की धमकी देता था। यह भी कहा गया कि 24.6.2010 को सुबह लगभग 7 बजे उनके पति को पप्पू दास, महरू दास उर्फ अतवारी दास और मधुसूदन गुप्ता ने बुलाया और उसके बाद वे कहीं चले गए। लगभग 11:00 बजे उनके देवर (भाई-इन-लॉ) मनोज कुमार मंडल ने उनके पति के बारे में पूछा तो सूचना देने वाली ने कहा कि वह पप्पू दास और मधुसूदन दास के साथ निचेलाखारी की ओर गए हैं। इसके बाद वह मनोज कुमार मंडल और बेटे-पंकज कुमार के साथ निचेलाखारी की ओर गईं और जब वे ईंट भट्टा से लगभग 100 गज दूर थे, तो उन्होंने देखा कि पप्पू दास उनके पति को पेट में चाकू मार रहा है और मधुसूदन गुप्ता और सोमर दास तथा पप्पू की पत्नी उनके पति पर ईंट और पत्थर से हमला कर रहे हैं। जब वे घटना स्थल की ओर दौड़े तो हमलावरों ने भी उन पर चाकू, ईंट और पत्थर से हमला करने के लिए दौड़ लगाई लेकिन किसी तरह सूचना देने वाली पार्टी ने अपनी जान बचाई और अपने घर पहुंच गईं। इस बीच, मामला पुलिस के संज्ञान में आया जिसने घटना स्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की।

4. सूचना देने वाले की फर्दबयान के आधार पर, आरोपी व्यक्तियों पप्पू दास, मधुसूदन गुप्ता, सोमर दास और पप्पू दास की पत्नी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत एक औपचारिक एफ.आई.आर. दर्ज की गई।

5. मामले की जांच जांच अधिकारी द्वारा की गई, जिन्होंने जांच के बाद पप्पू दास और बंधनी देवी उर्फ बुद्धनी देवी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत चार्ज-शीट प्रस्तुत की।

6. इसके बाद अपराध का संज्ञान लिया गया और मामला सत्र न्यायालय में भेजा गया जहाँ से विद्वान जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-V, गिरिडीह के न्यायालय में परीक्षण और निपटान के लिए प्राप्त हुआ।

7. यहाँ यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि प्रारंभ में केवल पप्पू दास ही मामले में परीक्षण का सामना कर रहा था लेकिन बाद में बंधनी देवी उर्फ बुद्धनी देवी के खिलाफ भी चार्ज-शीट प्रस्तुत की गई। तदनुसार, उनके खिलाफ संज्ञान लिया गया और मामला सत्र न्यायालय में भेजा गया और वह सत्र परीक्षण संख्या 348/11 में परीक्षण का सामना कर रही थी। इसके बाद सत्र परीक्षण 348/11 को मूल सत्र परीक्षण संख्या 375/10 के साथ 11.04.2012 के आदेश द्वारा एकीकृत किया गया। तदनुसार, दोनों आरोपी व्यक्तियों अर्थात् पप्पू दास और बंधनी देवी उर्फ बुद्धनी देवी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत परीक्षण का सामना किया।

8. परीक्षण के दौरान, अभियोजन पक्ष ने कुल छह गवाहों का परीक्षण किया, अर्थात्, पी.डब्ल्यू.1- मनोज कुमार मंडल (मृतक का भाई), पीडब्ल्यू 2- पंकज कुमार मंडल (मृतक का बेटा), पीडब्ल्यू 3- बसुदेव प्रसाद मंडल (सुने हुए गवाह) जिन्होंने शव परीक्षण रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर को प्रमाणित किया जिसे प्रदर्शित किया गया है (प्रदर्श 2), पीडब्ल्यू 4- रेनू देवी- मृतक की पत्नी (मामले की सूचना देने वाली)। पीडब्ल्यू 5- सुनील कुमार सिंह (चिकित्सक जिन्होंने गुलाब मंडल के शव पर पोस्टमार्टम परीक्षा की) और पीडब्ल्यू 6- सुमन आनंद (मामले का जांच अधिकारी)।

9. परीक्षण न्यायालय ने गवाहों का साक्ष्य रिकॉर्ड करने, मुख्य परीक्षा और प्रतिपरीक्षण करने के बाद, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत आरोपी व्यक्तियों का बयान दर्ज किया और पाया कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोप सिद्ध हुए।

10. तदनुसार, अपीलकर्ताओं को दोषी पाया गया और उन्हें 20.04.2015 की अपीलित दोषसिद्धि के निर्णय के माध्यम से दोषी ठहराया गया और 21.04.2015 के सजा के आदेश के माध्यम से सजा सुनाई गई, जो कि वर्तमान अपील का विषय है।

11. उपरोक्त दोषसिद्धि का निर्णय और सजा का आदेश इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है कि क्या परीक्षण न्यायालय ने आरोपी व्यक्ति को दोषी ठहराते समय कोई अवैधता की है या नहीं?

12. श्री एस.के. मुर्ती, अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता, ने अपीलित दोषसिद्धि के निर्णय और सजा के आदेश को निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी है:

I. विद्वान परीक्षण न्यायालय ने इस तथ्य को समझने में त्रुटि की है कि सभी गवाह इच्छुक गवाह हैं, केवल जांच अधिकारी और डॉक्टर को छोड़कर। इसके अलावा, उनके बयान भी एक-दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए अपीलित दोषसिद्धि का निर्णय और सजा का आदेश रद्द और निरस्त किया जाना चाहिए।

II. घटना स्थल एक खुला क्षेत्र है और गिरिडीह नगर के भीतर स्थित है, जो घनी आबादी वाला क्षेत्र है और कथित अपराध दिन के उजाले में किया गया है लेकिन फिर भी किसी स्वतंत्र गवाह का परीक्षण नहीं किया गया और आठ चार्ज-शीट किए गए गवाहों में से केवल छह गवाहों का परीक्षण किया गया है और शेष दो चार्ज-शीट किए गए गवाह, अर्थात् जुगल किशोर मंडल और हीरालाल मंडल का परीक्षण नहीं किया गया जिसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, जिससे अभियोजन मामले के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

III. इस मामले में, अभियोजन पक्ष ने स्वतंत्र गवाहों के संस्करण पर भरोसा करने के बजाय अत्यधिक इच्छुक गवाहों की गवाही पर भरोसा किया है, जो मृतक की पत्नी, बेटे और भाई के अलावा कोई नहीं हैं, जिनके बयान में कई विरोधाभास हैं।

IV. सूचना देने वाले (पी.डब्ल्यू. 4) के अनुसार, लिखित रिपोर्ट पुलिस को घटना स्थल पर तब सौंपी गई जब पुलिस गांव आई जबकि मनोज कुमार मंडल (पी.डब्ल्यू. 1) और पंकज कुमार मंडल (पी.डब्ल्यू. 2) ने अपने बयान में कहा कि वे पुलिस स्टेशन गए और लिखित रिपोर्ट पुलिस को सौंपी। इसके अलावा, पी.डब्ल्यू. 6- मामले का जांच अधिकारी ने बयान दिया कि जब वे घटना स्थल से पुलिस स्टेशन लौटे तो उन्होंने पुलिस स्टेशन पर सूचना देने वाले को देखा और लिखित रिपोर्ट उन्हें सौंपी गई जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई, जिससे अभियोजन मामले पर गंभीर संदेह उत्पन्न होता है।

V. पी.डब्ल्यू. 1 ने पहली बार अदालत में घटना के बारे में बयान दिया इसलिए पी.डब्ल्यू. 1 के साक्ष्य से कोई भरोसा नहीं किया जाना चाहिए था।

VI. पी.डब्ल्यू. 2 ने अपनी प्रतिपरीक्षण में विशेष रूप से बयान दिया कि वह कथित घटना की तारीख और समय पर अपने स्कूल में था, इसलिए उसे घटना स्थल पर होना नहीं कहा जा सकता जब घटना हुई। इसलिए, उसे आंखों देखी गवाह नहीं माना जा सकता बल्कि अधिकतम वह सुनी-सुनाई गवाही देने वाला कहा जा सकता है लेकिन दोषसिद्धि का निर्णय उसके बयान पर भी आधारित है, इसलिए अपीलित दोषसिद्धि का निर्णय और सजा का आदेश रद्द और निरस्त किया जाना उचित है।

13. अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने उपरोक्त आधारों के आधार पर प्रस्तुत किया है कि दोषसिद्धि का निर्णय और सजा का आदेश कानून की दृष्टि में टिकाऊ नहीं है और इसलिए इसे रद्द और निरस्त किया जाना चाहिए।

14. दूसरी ओर, श्री विश्वनाथ राँय, विद्वान सहायक लोक अभियोजक जो प्रतिवादी-राज्य के लिए उपस्थित हैं, ने प्रस्तुत किया है कि अपीलित दोषसिद्धि का निर्णय और सजा का आदेश में कोई त्रुटि नहीं है क्योंकि विद्वान परीक्षण न्यायालय ने गवाहों की गवाही पर विचार करने के बाद अपीलित दोषसिद्धि का निर्णय और सजा का आदेश पारित किया है। उन्होंने अपीलित आदेश की रक्षा करते हुए निम्नलिखित आधार लिए हैं: -

I. सूचना देने वाली रेनू देवी ने अभियोजन मामले का पूरी तरह समर्थन किया है और उनकी गवाही अन्य गवाहों, अर्थात् बसुदेव मंडल, पंकज मंडल और मनोज कुमार मंडल की गवाही से भी समर्थित है।

II. पी. डब्ल्यू. 1, पी. डब्ल्यू. 2, पी. डब्ल्यू. 3 और पी. डब्ल्यू. 4 की गवाही बहुत अधिक संगत, सहायक और विश्वसनीय है कि पप्पू दास द्वारा किए गए हमले के कारण मृतक गुलाब मंडल की मृत्यु हुई।

III. इसके अलावा, पी.डब्ल्यू. 1, पी.डब्ल्यू. 2 और पी.डब्ल्यू. 4 घटना के आंखों देखे गवाह हैं और उन्होंने घटना के बारे में बताया है और इन सभी गवाहों की गवाही को पी.डब्ल्यू. 5- डॉक्टर द्वारा संपुष्ट किया गया है जिन्होंने गुलाब मंडल के शव पर कई पूर्व-मृत्यु चोटें, कटने की चोटें, फटी हुई चोटें और नीले निशान पाए हैं। इसके अलावा डॉक्टर ने यह भी कहा कि मृत्यु का कारण सिर, छाती, पेट और गर्दन की चोटें हैं जो तेज और चुभने वाली वस्तुओं जैसे चाकू से हुई हैं, जैसा कि आंखों देखे गवाहों द्वारा वर्णित किया गया है।

IV. रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आंखों देखे गवाहों की गवाही को नकारा जा सके और इसलिए अभियोजन पक्ष ने सभी उचित संदेहों से परे आरोप को सफलतापूर्वक सिद्ध किया है।

15. उपरोक्त आधारों के आधार पर विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने प्रस्तुत किया कि दोषसिद्धि का निर्णय और सजा का आदेश इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

16. हमने पक्षों के अधिवक्ताओं की सुनवाई की है, रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री को देखा है विशेष रूप से गवाहों की गवाही और विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को देखा है।

17. इस न्यायालय ने पक्षों की ओर से पेश किए गए तर्क पर विचार करने से पहले गवाहों के बयान पर विचार करने की प्रक्रिया शुरू की है, जैसा कि विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा दर्ज की गई गवाही में उल्लेखित है।

पी.डब्ल्यू. 1- मनोज कुमार मंडल, जो मृतक का भाई है, ने गवाही दी कि 24.06.2010 को जब वह सुबह 11 बजे अपने घर आया तो उसकी भाभी ने बताया कि उसका भाई पप्पू दास के साथ लखारी गया है जहाँ पप्पू और गुलाब साझेदारी में ईंटों का व्यवसाय चला रहे थे और पप्पू पर ₹30,000/- बकाया था, जिसे मांगने पर पप्पू उन्हें मारने की धमकी देता था। उसने आगे कहा कि जब वह रेनू देवी के साथ ईंट भट्टा की ओर जा रहा था, तो उसने देखा कि पप्पू दास चाकू से वार कर रहा है और उसकी पत्नी भी पीड़ित पर ईंट से हमला कर रही थी, जिस पर उन्होंने विरोध किया। इसके बाद आरोपी उनकी ओर दौड़े और इसलिए उन्हें अपने घर भागना पड़ा। उसने यह भी कहा कि महेश मंडल ने एक आवेदन तैयार किया जिसे पुलिस स्टेशन में दिया गया और आवेदन पर सूचना देने वाली रेनू देवी के हस्ताक्षर थे और उसने (मनोज कुमार मंडल) भी गवाह के रूप में अपना हस्ताक्षर किया। उसने लिखित रिपोर्ट को प्रमाणित किया जिसे प्रदर्श 1 के रूप में चिह्नित किया गया। प्रतिपरीक्षणमें, उसने स्वीकार किया कि वह गुलाब मंडल का भाई है और वह पहली बार अदालत में अपना बयान दे रहा है।

II. पी.डब्ल्यू. 2- पंकज कुमार मंडल ने गवाही दी कि 24.6.2010 को सुबह 11 बजे उसके चाचा मनोज कुमार मंडल आए और उसकी माँ से उसके पिता के बारे में पूछा, जिस पर उसने कहा कि वह पप्पू दास के साथ गया है। इसके बाद वह मनोज और रेनू देवी के साथ ईंट भट्टा (किल्न) के पास पहुँचा और देखा कि पप्पू उसके पिता (मृतक) को पीट रहा है और उसके पेट में चाकू मार रहा है और पप्पू की पत्नी उसके पिता पर ईंट से हमला कर रही है। उसके पिता मदद के लिए चिल्ला रहे थे, जिस पर वे उसे बचाने गए तब पप्पू दास और उसकी पत्नी ईंट और चाकू लेकर उनकी ओर दौड़े। वे अपने घर आए और फिर वह मनोज और रेनू देवी के साथ पुलिस स्टेशन गए जहाँ उसकी माँ ने पुलिस को लिखित रिपोर्ट दी जो महेश मंडल द्वारा तैयार की गई थी और उसकी माँ द्वारा हस्ताक्षरित थी। उसने आगे कहा कि उसके पिता और पप्पू साझेदार थे। प्रतिपरीक्षणमें तीसरे पैरा में उसने कहा कि घटना की तारीख और समय पर वह डीएवी स्कूल में था। उसने आगे कहा कि पुलिस ने भी घटना के बारे में उसका बयान दर्ज किया था।

III. पी.डब्ल्यू. 3- बसुदेव प्रसाद मंडल ने कहा कि 24.6.2010 को वह गाँव लखारी में था जहाँ उसने सुना कि गुलाब मंडल की हत्या कर दी गई है। वह घटना स्थल पर गया जहाँ उसे पुलिस मिली। पुलिस ने शव का कागज तैयार किया जिसे उसने हस्ताक्षर किया। अधिकारी-इन-चार्ज, सुमन आनंद ने कागज तैयार किया जो उसकी लेखनी और हस्ताक्षर में है जिसे प्रदर्श 2 के रूप में चिह्नित किया गया। उसने आगे कहा कि एक खून से सना चाकू भी शव के पास पाया गया था और ईंट भी बरामद की गई थी। कागज अधिकारी-इन-चार्ज, सुमन आनंद द्वारा तैयार किया गया था जिसे उसने हस्ताक्षर किया और प्रदर्श 3 के रूप में चिह्नित किया। इसके बाद पुलिस पप्पू दास के घर गई जहाँ जींस की पैंट और शर्ट बरामद हुई जिसमें खून का धब्बा पाया गया। कागज तैयार किया गया जो जांच अधिकारी, सुमन आनंद की लेखनी और हस्ताक्षर में है। प्रतिपरीक्षण में उसने कहा कि उसने घटना स्थल पर जब्ती सूची पर हस्ताक्षर किए हैं और जल्द सामग्री उसे पुलिस द्वारा दिखाई गई थी। उसने आगे कहा कि उसे सुमन दरोगा के साथ काम करने का अवसर मिला लेकिन वह स्थान याद नहीं कर सकता।

IV. पी.डब्ल्यू. 4 - रेनु देवी इस मामले की सूचना देने वाली हैं जिन्होंने गवाही दी कि घटना 26.06.2010 को हुई थी। उसके पति गुलाब मंडल और पप्पू दास ईंटों का व्यवसाय चला रहे थे जिसमें उसके पति ने ₹1 लाख का निवेश किया था और ₹30,000/- पप्पू दास द्वारा अदा किए जाने थे और जब उसके पति द्वारा मांग की गई तो ऐसी घटना हुई। उसने आगे कहा कि पप्पू सुबह 7:30 बजे उसके घर आया और उसके पति को ईंट भट्टा ले गया। देवर मनोज मंडल और बेटा पंकज कुमार मंडल आए और उसके पति के बारे में पूछा, फिर वे उसे खोजने गए और देखा कि पप्पू दास उसके पति के पेट पर चाकू मार रहा है और पप्पू दास की पत्नी ईंट से हमला कर रही है। जब उन्होंने शोर मचाया तो आरोपी उनकी ओर दौड़े, फिर वे अपने घर चले गए। उसने आगे कहा कि महेश प्रसाद मंडल वहाँ आए जिनसे उसने घटना के बारे में बताया। महेश प्रसाद मंडल ने लिखित रिपोर्ट तैयार की जिसे उसने हस्ताक्षरित किया। मनोज और पंकज ने भी लिखित रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए जिसे प्रदर्श 5 के रूप में चिह्नित किया गया। इस बीच, पुलिस घटना स्थल पर पहुँची और लिखित रिपोर्ट पुलिस को प्रस्तुत की तथा उसके पति को मृत पाया। पुलिस ने शव को पुलिस स्टेशन ले जाया। प्रतिपरीक्षण में उसने कहा कि उसने अपनी आँखों से घटना देखी है। जुगल किशोर मंडल, जो उसके ससुर हैं, ने इस घटना के बारे में सुना है। उसने आगे कहा कि उसे घटना के बारे में एक घंटे बाद पता चला।

V. पी.डब्ल्यू. 5- सुनील कुमार सिंह, जो सदर अस्पताल, गिरिडीह में पदस्थ चिकित्सा अधिकारी हैं, ने अपने साक्ष्य में कहा कि 25.06.2010 को लगभग 12:15 बजे उन्होंने गुलाब मंडल, जो जुगल मंडल का पुत्र है, के शव पर पोस्टमार्टम परीक्षा की और जांच करने पर पाया कि उसके निचले अंगों में कठोरता उपस्थित थी। उनके शरीर पर कुछ पूर्व-मृत्यु चोटें भी पाई गईं:

(1) 1 1/2" x 1" x पेट की गहराई में बाईं ओर के सामने के पेट के पास नाभि के बगल में कटने की चोट।

(2) 1/4" x 1/4" x मांस की गहराई में बाईं ओर के नीचे के होंठ के पास कटने की चोट।

(3) 1" x 1/4" x उपास्थि की गहराई में बाईं कान पर कटने की चोट।

(4) 1" x 1/2" x मांस की गहराई में बाईं कान के पीछे कटने की चोट।

(5) 1/2" x 1/2" x मांस की गहराई में ठोड़ी के नीचे फटी हुई चोट।

(6) 2" x 1" x मांस की गहराई में बाईं ओसिपिटल क्षेत्र में फटी हुई चोट।

(7) मुंह से खून बहना।

(8) गर्दन के सामने 4" x 4" का नीला निशान और खोपड़ी की छानबीन करने पर खोपड़ी के नीचे हेमेटोमा पाया गया।

खोपड़ी के गुहा में सभी मस्तिष्क गोलार्धों में उपद्रव हेमेटोमा पाया गया। गर्दन के सामने और साइड पर त्वचा के नीचे हेमेटोमा पाया गया। श्वसन उपास्थियाँ और थायरॉइड टूटे हुए थे। बाएं फेफड़े में रक्त का थक्का था और छाती की गुहा में रक्त का थक्का पाया गया। पेट और प्लीहा कटे हुए थे, छोटी आंत और मेसेंटरी को चोटें आई थीं। पेट की गुहा में रक्त का थक्का - पीला। दिल - खाली। पेट में लगभग 15 मिलीलीटर पीला भूरा तरल। मूत्राशय - खाली।

उसने यह राय दी कि मृत्यु का समय लगभग 24 से 36 घंटे है और मृत्यु का कारण सिर, छाती, पेट की चोटें, गला घोटने से गर्दन की चोट है और चोट नंबर 1 से 4 से संबंधित हथियार तेज और चुभने वाली वस्तु जैसे चाकू हो सकता है। बाकी चोटों के लिए, वे कठोर और कुंद पदार्थ जैसे ईंट और पत्थर हो सकते हैं। सभी चोटें सामान्य परिस्थितियों में किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त हैं। उसने आगे कहा कि उसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को प्रमाणित किया जो उसकी लेखनी और हस्ताक्षर में है जिसे प्रदर्श 5 के रूप में चिह्नित किया गया।

प्रतिपरीक्षण में उसने कहा कि उसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह उल्लेख नहीं किया कि चोट नंबर 1 से 4 चाकू द्वारा हो सकती हैं और ऐसी चोटें तेज और चुभने वाले पत्थर पर गिरने से नहीं हो सकती हैं।

VI. पी.डब्ल्यू 6- सुमन आनंद इस मामले का जांच अधिकारी है जिसने गवाही दी कि 24.06.2010 को वह मप्फसिल पी.एस. का अधिकारी-इन-चार्ज था और दोपहर 12:45 बजे उसे सूचना मिली कि गाँव लखारी में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। इस सूचना मिलने पर वह गाँव लखारी गया और वहाँ गुलाब मंडल का शव पाया। गुलाब मंडल का शव परीक्षण रिपोर्ट तैयार किया गया जो उसकी लेखनी और हस्ताक्षर में है और इसे हीरालाल राजक और बसुदेव मंडल द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है जिसे प्रदर्श 2 के रूप में चिह्नित किया गया। इसके अलावा, उसने हीरालाल राजक और बसुदेव मंडल की उपस्थिति में चाकू और खून लगे ईट को जब्त किया। जब्ती सूची तैयार की गई जो उसकी लेखनी और हस्ताक्षर में है जिसे पहले प्रदर्श 3 के रूप में चिह्नित किया गया था और पप्पू दास के घर की तलाशी लेने पर खून लगे पैट और शर्ट जब्त किए गए जो दो गवाहों की उपस्थिति में किए गए थे, जिसे उसने प्रदर्श 4 के रूप में प्रमाणित किया। इसके बाद उसने जब्ती गवाहों का बयान दर्ज किया, घटना स्थल का निरीक्षण किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस स्टेशन लौटने पर, उसने मृतक गुलाब मंडल की पत्नी रेनू देवी से मुलाकात की और आरोपी पप्पू दास ने पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण कर दिया।

रेनू देवी की लिखित रिपोर्ट के आधार पर मप्फसिल थाना मामला संख्या 174/10 भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दर्ज किया गया। उसने मामले की जांच का कार्यभार लिया। लिखित रिपोर्ट को प्रदर्श 1 के रूप में चिह्नित किया गया है और उसने इस पर अपने लेखन और हस्ताक्षर को प्रमाणित किया जिसे प्रदर्श 6 के रूप में चिह्नित किया गया। इसके अलावा, उसने गवाहों रेनू देवी, महेश मंडल, मनोज मंडल और पंकज कुमार का बयान दर्ज किया तथा आरोपी पप्पू दास का बयान भी दर्ज किया जिसने स्वीकार किया कि उसने गुलाब मंडल को चाकू से मारा क्योंकि उसकी पत्नी पर उसकी बुरी नजर थी। उसने ए.एस.आई. रामप्रवेश सिंह का बयान भी दर्ज किया। उसने जुगल किशोर मंडल का बयान भी दर्ज किया। उसने औपचारिक एफआईआर को प्रमाणित किया जो एएसआई रामप्रवेश सिंह द्वारा लिखी गई थी जिसमें उसका हस्ताक्षर भी था जिसे प्रदर्श 7 के रूप में चिह्नित किया गया।

प्रतिपरीक्षण में उसने कहा कि यह तथ्य नहीं है कि उसने पंकज मंडल, बसुदेव मंडल और रेनू देवी का सही बयान दर्ज नहीं किया है और यह भी इनकार किया कि आरोपी पुलिस स्टेशन पर गिरफ्तार नहीं हुआ था तथा यह तथ्य नहीं है कि आरोपी ने उससे यह नहीं कहा कि उसने

मृतक को इसलिए मारा क्योंकि उसकी पत्नी पर उसकी बुरी नजर थी। उसने अपने बयान में आगे कहा कि जब्त सामग्री अदालत में उपस्थित नहीं है।

18. अपीलित निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि विद्वान परीक्षण न्यायालय ने पी.डब्ल्यू 1, 2 और 4 की गवाही पर विचार करके दोषसिद्धि की है, इसलिए इस न्यायालय को यह विचार करना आवश्यक है कि क्या पी.डब्ल्यू 1, 2 और 4 की गवाही विश्वसनीय है या नहीं ताकि अपीलकर्ताओं के खिलाफ दोषसिद्धि का निर्णय और सजा का आदेश पारित किया जा सके।

19. इस न्यायालय ने उक्त मुद्दे का आकलन करने के लिए पी.डब्ल्यू 1, पी.डब्ल्यू 2 और पी.डब्ल्यू 4 की गवाहियों की जांच की है, जो कथित रूप से घटना के आंखों देखे गवाह हैं, ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि क्या ये गवाह विश्वसनीय हैं या नहीं।

20. जहां तक पी.डब्ल्यू 1 का संबंध है, यह एक स्वीकृत तथ्य है कि पी.डब्ल्यू 1 ने परीक्षण न्यायालय में पहली बार घटना के बारे में गवाही दी है और इस गवाह का कोई बयान अभियोजन एजेंसी द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत कभी दर्ज नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में, न्यायालय को उसकी गवाही पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 161 और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज बयान को गवाह द्वारा परीक्षण न्यायालय में दी गई गवाही के विपरीत या समर्थन के रूप में लिया जाना चाहिए। ऐसे बयान की अनुपस्थिति में, आरोपी को गवाही का खंडन करने का अवसर उपलब्ध नहीं होता। इस प्रकार की गवाही पर भरोसा करने के लिए अन्य गवाहों की गवाही और रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य से समर्थन आवश्यक है।

21. इसके अलावा, अभियोजन पक्ष द्वारा यह कारण नहीं बताया गया है कि इस गवाह का बयान आपराधिक प्रक्रिया संहिता 161 के तहत क्यों नहीं लिया गया और वह पहली बार अदालत में आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ गवाही देने आया है।

22. यह स्थापित कानूनी सिद्धांत है कि यदि गवाह किसी विशेष आरोपी को अपराध में शामिल नहीं करता है जब उसका बयान आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज किया जा रहा हो और वह पहली बार अदालत में गवाही देता है, तो आरोपी को संदेह का लाभ प्राप्त होता है।

23. इस न्यायालय ने पी.डब्ल्यू 2 (मृतक का पुत्र) की गवाही की जांच करते समय पाया कि उसकी मुख्य परीक्षा और प्रतिपरीक्षण के बीच महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं। मुख्य परीक्षा में उसने कहा था कि उसने अपीलकर्ता पप्पू द्वारा अपने पिता (मृतक) के शरीर पर चाकू से चोट पहुँचाने की घटना देखी थी और उसने आगे कहा था कि उसने देखा था कि पप्पू की पत्नी उसके पिता पर ईंट से हमला कर रही थी और उसके पिता मदद के लिए चिल्ला रहे थे, जिस पर वे उसे

बचाने दौड़े लेकिन आरोपी व्यक्तियों ने उनका पीछा किया इसलिए वह अपने घर भाग गया। लेकिन प्रतिपरीक्षण में उसने मुख्य परीक्षा में कहे गए विपरीत बयान दिया और कहा कि कथित तारीख और समय पर वह डीएवी स्कूल में था।

24. इस न्यायालय का विचार है कि गवाही के विश्लेषण के आधार पर, जैसे कि मुख्य परीक्षा और प्रतिपरीक्षण में, पी.डब्ल्यू. 2 को आंखों देखे गवाह नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उसने प्रतिपरीक्षण में विरोधाभासी बयान दिया है और इसलिए, जो कुछ भी उसने मुख्य परीक्षा में कहा है, उसे विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता और उसकी गवाही को अपीलकर्ता की दोषसिद्धि के लिए नहीं लिया जा सकता क्योंकि घटना स्थल पर उसकी उपस्थिति उसके प्रतिपरीक्षणमें दिए गए बयान के अनुसार संदिग्ध है।

25. गवाहों की गवाहियों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान मामला रेनू देवी (पी.डब्ल्यू. 4) की लिखित रिपोर्ट के आधार पर स्थापित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि उसके पति गुलाब मंडल (मृतक) पप्पू दास के साथ ईंटों का व्यवसाय चला रहे थे। व्यवसाय में पप्पू दास पर ₹30,000/- बकाया हो गए थे और जब इस राशि की मांग की गई, तो पप्पू उन्हें मारने की धमकी देता था। 24.6.2010 को सुबह लगभग 7:00 बजे उसके पति को पप्पू दास और मकसूदन गुप्ता ने बुलाया, लेकिन जब कुछ समय बाद उसके पति वापस नहीं आए, तो वह अपने देवर मनोज मंडल और बेटे पंकज मंडल के साथ लखारी गाँव की ओर उन्हें खोजने गई और जब वे भट्टा के पास पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि पप्पू दास उसके पति के पेट में चाकू मार रहा है और उसकी पत्नी ईंट और पत्थर से हमला कर रही है। इस पर उसने चिल्लाया लेकिन आरोपी व्यक्तियों ने उन पर हमला करने का इरादा रखते हुए उनका पीछा किया, हालाँकि सूचना देने वाली वहाँ से अपने घर भागने में सफल रही।

26. इसके अलावा, सूचना देने वाली (पी.डब्ल्यू. 4) की गवाही से यह भी स्पष्ट होता है कि लिखित रिपोर्ट पुलिस को घटना स्थल पर तब सौंपी गई जब पुलिस गाँव आई, जबकि मनोज मंडल (पी.डब्ल्यू. 1) और पंकज मंडल (पी.डब्ल्यू. 2) ने कहा कि वे पुलिस स्टेशन गए और पुलिस को लिखित रिपोर्ट सौंपी। इसके अलावा, पी.डब्ल्यू. 6- मामले का जांच अधिकारी ने गवाही दी कि जब वे घटना स्थल से पुलिस स्टेशन लौटे तो उन्होंने पुलिस स्टेशन पर सूचना देने वाली को देखा और लिखित रिपोर्ट उन्हें सौंपी गई जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई।

27. इसलिए, सूचना देने वाली (पी.डब्ल्यू. 4) की पूरी गवाही को ध्यान में रखते हुए, हम यह मानते हैं कि पी.डब्ल्यू. 4 को विश्वसनीय या भरोसेमंद गवाह नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसकी गवाही विरोधाभासों से भरी हुई है।

28. इस प्रकार, तथ्यों के संपूर्णता में यह स्पष्ट है कि गवाहों की गवाहियों के बीच विरोधाभास हैं जो अभियोजन पक्ष के मामले पर गंभीर संदेह उत्पन्न करते हैं और यह इस न्यायालय के मन में विश्वास पैदा नहीं करते हैं।

29. अब अपीलित दोषसिद्धि के निर्णय और सजा के आदेश पर आते हुए, अपीलित निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि पी.डब्ल्यू. 1, 2 और 4 की गवाही के आधार पर, जिन्हें आंखों देखे गवाह माना गया है और जिन्हें पी.डब्ल्यू. 5 की गवाही द्वारा समर्थन दिया गया है, दोषसिद्धि का निर्णय पारित किया गया है।

30. कानून यह स्पष्ट रूप से स्थापित है कि यदि गवाहों की गवाही विश्वसनीय हो तो दोषसिद्धि हो सकती है। लेकिन उस गवाही की विश्वसनीयता उसकी विचारणीयता के लिए आवश्यक होती है ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि उस प्रकार के गवाह की गवाही विश्वसनीय कही जा सकती है।

31. यहाँ, पी.डब्ल्यू. 2 ने मुख्य परीक्षा में यह बताया था कि उसने अपराध होते देखा था और इसलिए, उक्त गवाही के आधार पर, जैसा कि मुख्य परीक्षा में दर्ज किया गया था, विद्वान परीक्षण न्यायालय ने पी.डब्ल्यू. 2 को आंखों देखे गवाह माना। लेकिन विद्वान परीक्षण न्यायालय ने उस गवाही पर विचार करने में असफल रही जो उसके प्रतिपरीक्षण में दर्ज की गई थी, जिसमें उसने अपनी मुख्य परीक्षा में दिए गए बयान के विपरीत बयान दिया और कहा कि घटना की तारीख और समय पर वह अपने स्कूल में था। इसके अलावा, विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा यह कोई कारण नहीं बताया गया कि उसने पी.डब्ल्यू. 2 द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षणमें दिए गए बयान पर विचार क्यों नहीं किया।

32. इसलिए, हमारे विचार के अनुसार, पी.डब्ल्यू. 2 की गवाही को विश्वसनीय और भरोसेमंद गवाह नहीं कहा जा सकता है ताकि आरोपी व्यक्तियों को दोषी ठहराया जा सके। यदि पी.डब्ल्यू. 2 की गवाही को ही अविश्वसनीय माना गया है, तो अन्य गवाहों की गवाही से उसके समर्थन का कोई प्रश्न नहीं उठता।

33. इस प्रकार, ऊपर की चर्चा से यह स्पष्ट है कि सूचना देने वाली पी.डब्ल्यू. 2 को आंखों देखे गवाह नहीं माना जा सकता है।

34. इसके अलावा, पी.डब्ल्यू. 1 जो एक और कथित आंखों देखे गवाह है, उसे भी पूरी तरह से विश्वसनीय गवाह नहीं कहा जा सकता क्योंकि पी.डब्ल्यू. 1 ने इस न्यायालय में पहली बार गवाही दी है और पुलिस द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत कोई बयान दर्ज नहीं

किया गया है, इसलिए उसकी गवाही पर आरोप को सभी उचित संदेहों से परे सिद्ध नहीं कहा जा सकता।

35. इसके अतिरिक्त, जहां तक पी.डब्ल्यू. 4 (सूचना देने वाली) की गवाही का संबंध है, वह अपनी गवाही में असंगत है और उसकी गवाही में महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं क्योंकि उसने कहा कि लिखित रिपोर्ट पुलिस को घटना स्थल पर सौंपी गई जब पुलिस गाँव आई, जबकि पंकज मंडल (पी.डब्ल्यू. 2) और मनोज मंडल (पी.डब्ल्यू. 1) ने कहा कि वे पुलिस स्टेशन गए और पुलिस को लिखित रिपोर्ट सौंपी। इसके अलावा, पी.डब्ल्यू. 6- मामले का जांच अधिकारी ने गवाही दी कि जब वे घटना स्थल से पुलिस स्टेशन लौटे तो उन्होंने पुलिस स्टेशन पर सूचना देने वाली को देखा और लिखित रिपोर्ट उन्हें सौंपी गई जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। इसलिए, पी.डब्ल्यू. 4 (सूचना देने वाली) की गवाही की विश्वसनीयता प्रश्न में है। आगे, उसने अपनी गवाही में कहा कि वह अपने बेटे (पी.डब्ल्यू. 2) और पी.डब्ल्यू. 1 के साथ अपने पति की खोज में गई और पाया कि आरोपी पप्पू उसके पति पर चाकू मार रहा था, लेकिन पी.डब्ल्यू. 2 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से कहा कि घटना के समय वह डीएवी स्कूल में था।

36. हालांकि, यह स्थापित कानूनी सिद्धांत है कि आंखों देखे गवाहों के साक्ष्य में छोटे परिवर्तन और विरोधाभास आरोपी के पक्ष में संदेह का लाभ नहीं देते हैं, लेकिन जब अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य में विरोधाभास अभियोजन मामले के लिए घातक साबित होते हैं, तो वे मामले की जड़ तक पहुँचते हैं और ऐसे मामलों में आरोपी को संदेह का लाभ मिलता है।

37. इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **कृष्णागोवदा बनाम कर्नाटका राज्य [(2017) 13 एससीसी 98]** मामले में दिए गए निर्णय का उल्लेख किया जा सकता है, जिसमें पैराग्राफ-32 और 33 में निम्नलिखित कहा गया है: -

“32. --- --- आंखों देखे गवाहों के साक्ष्य में छोटे परिवर्तन और विरोधाभास आरोपी के पक्ष में संदेह का लाभ नहीं देते हैं, लेकिन जब अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य में विरोधाभास अभियोजन मामले के लिए घातक साबित होते हैं, तो वे मामले की जड़ तक पहुँचते हैं और ऐसे मामलों में आरोपी को संदेह का लाभ मिलता है।

33. न्यायालय का कर्तव्य है कि वह रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य की विश्वसनीयता पर विचार करे। जैसा कि बेंटहम ने कहा है, “गवाह न्याय का आंखें और कान होते हैं।--- ---”

38. इसके अलावा, यह स्थापित कानूनी सिद्धांत है कि यदि अभियोजन गवाहों के प्रतिपरीक्षण के परिणाम से आरोपी अपनी रक्षा की संभावना स्थापित कर सकता है और यदि आरोपी द्वारा संभावना स्थापित की गई, तो यह उसे संदेह का लाभ देने का अधिकार देता है।

39. इस संदर्भ में, भिकम सारण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(1953) 2 एससीसी 560] मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का उल्लेख किया जा सकता है, जिसमें पैराग्राफ-16 में कहा गया है: -

“16. यह महत्वपूर्ण है कि अपीलकर्ता ने अपनी रक्षा में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया, बल्कि केवल अपने बचाव को स्थापित करने के लिए अभियोजन गवाहों के साक्ष्य पर निर्भर किया। उसे अपनी रक्षा को उस तरीके से सकारात्मक रूप से स्थापित करने की आवश्यकता नहीं थी जिस तरह से अभियोजन को अपना मामला स्थापित करना था। यदि अभियोजन गवाहों के प्रतिपरीक्षण के परिणामस्वरूप वह अपनी रक्षा की संभावना स्थापित कर सकता है, तो यह उसके उद्देश्यों के लिए पर्याप्त था, क्योंकि यदि ऐसी संभावना उसके द्वारा स्थापित की गई, तो यह वास्तव में उसे संदेह का लाभ देने का अधिकार देती है, क्योंकि ऐसी संभावना अभियोजन मामले को सभी उचित संदेहों से परे स्थापित होने से रोकती है।”

40. यहाँ, पी.डब्ल्यू. 2 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा कि उसने घटना देखी थी लेकिन प्रतिपरीक्षण में उसने स्पष्ट रूप से कहा कि घटना के समय वह स्कूल में था।

41. इसलिए, भिकम सारण (उपर्युक्त) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बताया गए सिद्धांत के अनुसार, आरोपी व्यक्तियों को संदेह का लाभ प्राप्त होता है लेकिन विद्वान परीक्षण न्यायालय ने पी.डब्ल्यू. 2 की प्रतिपरीक्षण में दी गई गवाही पर विचार नहीं किया। इसलिए, इस आधार पर भी अपीलित दोषसिद्धि का निर्णय इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता रखता है।

42. रिकॉर्ड के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि हालांकि जांच अधिकारी ने अभियोजन पक्ष के संस्करण का समर्थन किया है और उसने कहा कि उसने घटना स्थल से खून लगे चाकू और पप्पू दास के खून लगे कपड़े जब्त किए थे और जब्ती सूची तैयार की गई थी, लेकिन उपरोक्त वस्तु कभी भी परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई।

43. इस प्रकार, अभियोजन पक्ष को आरोप सिद्ध करने में विफल कहा जा सकता है क्योंकि उसने अपराध का हथियार परीक्षण न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया और न ही उक्त हथियार को फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में परीक्षा के लिए भेजा गया।

44. चूंकि अपराध के हथियार और आरोपी के खून लगे कपड़े का परीक्षण न्यायालय में न प्रस्तुत करना अभियोजन पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण चूक मानी जाती है, इसलिए बिना ठोस साक्ष्य के आरोपी व्यक्तियों की स्वतंत्रता को सीमित करना सुरक्षित नहीं होगा।

45. इसके अलावा, यह स्थापित कानूनी स्थिति है कि आपराधिक परीक्षण में, जब तक अभियोजन आरोपी की दोषिता को सभी उचित संदेहों से परे स्थापित नहीं करता, तब तक आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता और एक आपराधिक न्यायालय अपीलकर्ताओं की आजीवन स्वतंत्रता को छीनने का जोखिम नहीं उठा सकता बिना यह सुनिश्चित किए कि अपीलकर्ता वास्तव में अपराधी था।

46. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई निर्णयों में यह सिद्धांत प्रस्तुत किया है कि आपराधिक परीक्षण में यदि आरोप सभी उचित संदेहों से परे सिद्ध नहीं होता है तो कोई भी दोषसिद्धि नहीं हो सकती। जैसा कि रंग बहादुर सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(2000) 3 एससीसी 454] मामले में कहा गया है, जिसमें पैराग्राफ-22 में निम्नलिखित कहा गया है: -

“22. इस मामले में अपीलकर्ताओं की संलिप्तता के संबंध में न्यायालय द्वारा रखे जाने वाले संदेह की मात्रा उचित संदेह के स्तर से कहीं अधिक है। हम जानते हैं कि इस प्रकार के मामले में आरोपी को बरी करना सभी संबंधित पक्षों के लिए संतोष का विषय नहीं है। साथ ही, हम उस समय-परीक्षित नियम को याद करते हैं कि एक दोषी व्यक्ति का बरी होना एक निर्दोष व्यक्ति की दोषसिद्धि पर प्राथमिकता होनी चाहिए। जब तक अभियोजन पक्ष आरोपी की दोषिता को सभी उचित संदेहों से परे सिद्ध नहीं करता, तब तक आरोपी पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती। एक आपराधिक न्यायालय अपीलकर्ताओं की स्वतंत्रता, आजीवन स्वतंत्रता, को छीनने का जोखिम नहीं उठा सकता जब तक कि उसके पास यह सुनिश्चित करने का कम से कम उचित स्तर न हो कि अपीलकर्ता वास्तव में अपराधी थे। हम वास्तव में अपीलकर्ताओं की अपराध में संलिप्तता के बारे में संदेह रखते हैं।”

47. इसी प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कृष्णगोवदा एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य (उपर्युक्त) मामले में पैराग्राफ-26 में निम्नलिखित कहा है: -

“26. अभियोजन गवाहों के साक्ष्य और उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों का अध्ययन करने के बाद हमें लगता है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को समझने में विफलता दिखाई है कि आरोपी की दोषिता को सभी उचित संदेहों से परे सिद्ध करना आवश्यक है और यह एक क्लासिक मामला है जहाँ परीक्षण के प्रत्येक चरण में जांच एजेंसी की ओर से चूक हुई और गवाहों का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है, जो कभी भी

दोषसिद्धि का आधार नहीं हो सकता। अपराधिक न्यायशास्त्र का मूल सिद्धांत यह है कि आरोपी को निर्दोष माना जाता है जब तक उसकी दोषिता सभी उचित संदेहों से परे सिद्ध नहीं होती।”

48. जहां तक अपीलकर्ताओं के आचरण का संबंध है, अपीलकर्ताओं की ओर से यह कहा गया है कि यह विश्वास करना कठिन है कि सूचना देने वाली, उसके देवर (मृतक का भाई) और बेटा आरोपी पप्पू दास द्वारा उपयोग किए गए चाकू को देखकर डर गए और आरोपी व्यक्तियों द्वारा पीछा किए जाने पर अपने घर लौट गए और यहां तक कि घटना स्थल से लौटते समय सूचना देने वाली और उनके परिवार के सदस्यों, जो मृतक की पत्नी, बेटा और भाई हैं, ने शोर नहीं मचाया। इसलिए सूचना देने वाली और उनके परिवार के आचरण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अभियोजन कहानी संदिग्ध है।

49. इस न्यायालय ने उपरोक्त प्रस्तुतियों पर विचार करने के लिए पी.डब्ल्यू 1, 2 और 4 की गवाहियों को पुनः देखना उचित समझा। उनकी गवाहियों में पी.डब्ल्यू 1, 2 और 4 ने कहा कि जब उन्हें अपीलकर्ताओं द्वारा पीछा किया गया तो वे घटना स्थल से भाग गए, मृतक को घटना स्थल पर छोड़ दिया और वहां शोर नहीं मचाया तथा मृतक को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।

50. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लाहू कमलाकर पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में, जो (2013) 6 एससीसी 417 में रिपोर्ट किया गया है, यह अवलोकन किया है कि कुछ अपराधों के गवाह डर के कारण घटना स्थल से भाग सकते हैं और स्थान छोड़ सकते हैं, लेकिन न्यायालय को यह ध्यान में रखना चाहिए कि विभिन्न गवाह विभिन्न परिस्थितियों में अलग-अलग प्रतिक्रिया देते हैं। जबकि इस सिद्धांत को ध्यान में रखना आवश्यक है, यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि यदि गवाह का आचरण इतना अस्वाभाविक है और स्वीकार्य मानव व्यवहार के अनुसार नहीं है, तो उसकी गवाही संदिग्ध हो जाती है और उसे अस्वीकार किया जा सकता है। उपरोक्त निर्णय का प्रासंगिक पैराग्राफ यहाँ उद्धृत किया जा रहा है: -

“26. उपरोक्त उद्घोषणाओं से यह स्पष्ट है कि कुछ अपराधों के गवाह डर के कारण घटना स्थल से भाग सकते हैं और यदि उनके परीक्षण में कोई देरी होती है, तो उनकी गवाही को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, न्यायालय को यह ध्यान में रखना चाहिए कि विभिन्न गवाह विभिन्न परिस्थितियों में अलग-अलग प्रतिक्रिया देते हैं। कुछ गवाह सदमे में चले जाते हैं, कुछ भ्रमित हो जाते हैं, कुछ चिल्लाने लगते हैं और कुछ घटना स्थल से भाग जाते हैं और फिर भी कुछ जो साहस और विश्वास रखते हैं, या तो

एफआईआर दर्ज कराने के लिए आगे आते हैं या तुरंत अपनी जांच कराते हैं। इस प्रकार, यह व्यक्तियों के बीच भिन्नता होती है। मानव प्रतिक्रिया में एकरूपता नहीं हो सकती। जबकि इस सिद्धांत को ध्यान में रखना आवश्यक है, **यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि यदि गवाह का आचरण इतना अस्वाभाविक है और स्वीकार्य मानव व्यवहार के अनुसार नहीं है, तो उसकी गवाही संदिग्ध हो जाती है और उसे अस्वीकार किया जा सकता है।**

51. इस न्यायालय ने कथित आंखों देखे गवाहों की गवाही की निकटता से जांच करने पर पाया कि इस मामले में सूचना देने वाली और उसके परिवार के सदस्यों का आचरण उस समय स्वाभाविक नहीं था जब उन्होंने उक्त अपराध देखा। इसके अलावा, रिकॉर्ड से यह स्पष्ट होता है कि पी.डब्ल्यू. 1, 2 और 4 मृतक के सबसे करीबी सदस्य हैं और ऐसी स्थिति में उनके लिए यह स्वीकार्य नहीं है कि उन्होंने मृतक को बचाने की कोशिश नहीं की।

52. इसके अलावा, उनकी गवाहियों के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि घटना स्थल से घर की ओर जाते समय उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा या उन्होंने शोर नहीं मचाया, इसलिए इस संदर्भ में उनकी गवाही संदिग्ध प्रतीत होती है और अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर करती है।

53. इस न्यायालय ने पी.डब्ल्यू. 1, 2 और 4 की गवाही का मूल्यांकन करते हुए निष्कर्ष निकाला है कि पी.डब्ल्यू. 2 की गवाही को आंखों देखे गवाह के रूप में नहीं माना जा सकता और पी.डब्ल्यू. 1 और 4 की गवाही विश्वसनीय और भरोसेमंद नहीं है। लेकिन विद्वान परीक्षण न्यायालय ने पी.डब्ल्यू. 1, 2 और 4 की गवाही पर विचार करके दोषसिद्धि पर आधारित किया है, इसलिए हमारे विचार के अनुसार अपीलित दोषसिद्धि का निर्णय उचित नहीं कहा जा सकता।

54. हम तथ्यों और परिस्थितियों की संपूर्णता को देखते हुए और ऊपर की चर्चा के अनुसार यह मानते हैं कि अपीलित दोषसिद्धि/सजा में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है।

55. तदनुसार, 20.04.2015 की दोषसिद्धि का निर्णय और 21.04.2015 का सजा का आदेश, जो विद्वान जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-V, गिरिडीह द्वारा सत्र परीक्षण मामला संख्या 375/2010 में पारित किए गए थे, को यहाँ रद्द और निरस्त किया जाता है।

56. परिणामस्वरूप, वर्तमान अपील स्वीकार की जाती है।

57. इसके परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता संख्या 1, अर्थात् पप्पू रवीदास उर्फ पप्पू दास को उसके आपराधिक दायित्व से मुक्त किया जाता है और उसे तुरंत न्यायिक हिरासत से रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, यदि किसी अन्य मामलों में आवश्यक न हो। अपीलकर्ता संख्या 2, अर्थात् बंधनी देवी उर्फ बुद्धनी देवी को भी उसके आपराधिक दायित्व से मुक्त किया जाता है क्योंकि वह

पहले से ही जमानत पर है, इसलिए उसकी रिहाई के लिए कोई अलग निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है।

58. इस आदेश/निर्णय को संबंधित न्यायालय में तुरंत संप्रेषित किया जाए, साथ ही निचली अदालत के रिकॉर्ड के साथ।

मैं सहमत हूँ

(न्यायमूर्ति नवनीत कुमार)

(न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद)

(न्यायमूर्ति नवनीत कुमार)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

तारीख: 19/12/2023

आलंकार/ एएफआर

यह अनुवाद पियूष आनंद, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है।